

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिर पर ब्याज दरों में कटौती करने से मना करने के कारण कम वृद्धि का दोष मड़ा गया है, किंतु यह मुद्रा स्फीति की आधी कहानी है। दूसरी आधी कहानी एक भयानक प्रकृति की है। मतभेद होने पर प्रत्येक सरकार खाद्य वस्तुओं के मूल्य प्राकृतिक रूप से कम करके मुद्रा स्फीति की दर कम दर्शाने का प्रयास करती है ताकि किसी प्रकार की जांच से बचा जा सके। पिछले एक दशक में सरकारी नितियों के कारण, किसानों को उनकी फसलों के लिए मिलने वाला कृषि मूल्य लगभग रू. 10 लाख करोड़ से भी कम कर दिया गया है। इसी अवधि के लिए कृषि क्षेत्र को दी गई आर्थिक सहायता की राशि इससे कई गुना अधिक है।

कड़े रूप से निर्यात पर प्रतिबंध (गेहूं, चावल, कपास, प्याज, आलू आदि) और खाद्य वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, बटर ऑयल, दालों, मक्का, प्याज आदि का निर्यात बढ़ाकर किसानों को मूर्ख बनाया जाता है कि वे दालों की कमी को दूर करने के लिए अफ्रीका जैसे देशों में दालें उगाएँ ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। यह तब है जबकि हमारा राष्ट्रीय एजेंडा 'मेक इन इंडिया' है। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय ने 5 लाख मैट्रिक टन मक्का के आयात की अनुमति दे दी है। इसके विपरीत, पशुपालन उद्योग और डेरी क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन्हीं क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएँ और गैर संगठित किसान भयंकर सूखे के वर्षों में भी अधिक उत्पादन होने के कारण अपने उत्पादन का कम मूल्य मिलने के कारण हानि उठा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यों से अधिकतम किसानों की आजीविका प्रमुख घटक नष्ट हो जाएगा।

इस वास्तविकता से नहीं बचा जा सकता की मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी इस मुद्दे पर मौन रहने के दोषी हैं, क्योंकि वे किसानों को खाद्य मुद्रा स्फीति नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक औजार के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि किसानों की सहायता करनी चाहिए। हमारा आर्थिक सहायता के औजार से और समान विकास के लक्ष्य को छोड़ देने के कारण देश के अधिकतम किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। खाद्य असुरक्षा, अपर्याप्त उत्पादन के कारण नहीं है, बल्कि संसाधनों के असंगत उपयोग और असमान वितरण के कारण है, जिसकी प्रमुख वजह खाद्य वस्तुओं तक आम आदमी की पहुंच न होना है।

किसानों की आजिविका का पुनरुत्थान

भारत कृषक समाज में श्री शेखर गुप्ता, अध्यक्ष एवम् मुख्य संपादक, द प्रिंट एवं पूर्व संपादक, इंडियन ऐक्सप्रेस द्वारा संचालित संगोष्ठी में डॉ० अरविन्द सुब्रमनियन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार द्वारा दिए गये भाषण का सार।

इस सरकार द्वारा तैयार प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण में उद्योग, सेवाओं और निर्माण तथा एक अध्याय में कृषि उपज विपणन समितियां (ऐ.पी.एम.सी.) पर ध्यान केन्द्रीत किया गया है, किंतु कृषि पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। अधिकतम लोगों की प्रतिक्रिया है कि हमने कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया। यह बिलकुल सही आलोचना है क्योंकि कृषि क्षेत्र की स्थिति यही ब्यान करती है।

भारत में लगातार 4 वर्षों से सामान्य से कम वर्षा हुई है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी गिरावट आई है, इस प्रकार कृषि आय पर कई प्रकार के संकट हैं। हमने प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था लेकिन हमने दूसरे सर्वेक्षण में कुछ सुधार किये लेकिन वे कृषि के लिए पर्याप्त नहीं थे। इन्हें आरंभ करने का दायित्व में लेता हूँ।

मैं कृषि विशेषज्ञ नहीं हूँ और न ही कोई ऐसी बात कहूँगा जो बिलकुल नई हो। मैं अतित में जाकर और कुछ विवादों से दूरी बनाते हुए इस विषय के परिपेक्ष्य में कुछ शैक्षिक बातें कहूँगा और अधिक प्रश्न उठाऊँगा और न की उत्तर दूँगा।

जब कृषि की बात करते हैं तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि कृषि क्यों ? इसका उत्तर बहुत से लोगों को ज्ञात होगा किंतु फिर भी क्यों के कारण बताये जाने चाहिएँ। भारत में कृषि अतिमहत्वपूर्ण बनाने के 2 प्रमुख पहलू हैं – पहला, मूलभूत और दूसरा, सहायक कारण। मूलभूत कारण है कि भारत का 49 प्रतिशत श्रमिक वर्ग अपनी आजिविका कृषि से अर्जित करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कृषि क्षेत्र के बारे में अथवा, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में वार्तालाप करता है, किंतु सत्य है कि भारतीय घरों में 50 प्रतिशत लोग कृषि से ही अपना गुजारा करते हैं।

वास्तव में यह एक बहुत बड़ा कार्य है। इसी प्रकार से 80 से 82 प्रतिशत भारतय निर्धन लोग कृषि/ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कृषि क्षेत्र ही खाद्य सुरक्षा है। उपलब्ध कराता है जो कि वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। सारांश यह है कि इतनी बड़ी संख्या बहुत महत्वपूर्ण और इतनी व्यापक है कि भारत किसी भी स्थिति में कृषि क्षेत्र को नकार नहीं सकता।

एक सहायक कारण भी है। कृषि अन्य क्षेत्रों को चलाने का एक प्रकार का वाहन और स्रोत भी है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यह सक्षम है। इस कारण इस पर ध्यान केन्द्रीत किया जाना चाहिए। अन्य उपायों से भी कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। सबसे पहले भारतीय मुद्रा स्फीति कृषि से ही प्रभावित होती है, जैसा की सभी परिचित हैं। पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आई है, मुद्रा स्फीति कम हुई किंतु भारतीय कृषि भारतीय मुद्रा स्फीति को ऊपर ही रखे हुए है। थौक और उपभोक्ता मूल्य दोनों से सूचकांक ऊपर हैं, जिस कारण कृषि और खाद्य वस्तुओं के मूल्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से वृद्धि दर प्रभावित होती है।

दूसरा, ब्याज दरें तब ही कम होंगी यदि कृषि मुद्रा स्फीति की दर कम है और ऐसा होने पर ही अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तीसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है कि कृषि का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कृषि मूल्यों की पावर के माध्यम से पड़ता है। हमें यह नहीं विचार करना की क्या यह अच्छा है अथवा बुरा। हम केवल यह जानते हैं कि कृषि क्षेत्र से निर्माण क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चौथे, कृषि को दिये गये ऋण से शेष पूरी अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

पांचवा, कृषि के भाग्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारत के शहरीकरण की गुणवत्ता पर पड़ेगा। क्या भारत का शहरीकरण अच्छा अथवा बुरा होगा, इस बात का निर्धारण कृषि क्षेत्र से आने वाले मजदूरों के प्रकार से होगा। ये आने वाले मजदूर क्या शिक्षित होंगे और क्या वे उच्च कौशल वाले कार्य कर सकेंगे ?

छटा, कृषि सामाजिक तनाव का भी एक साधन हो सकता है क्योंकि सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ही अर्थव्यवस्था की समस्या से गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे हैं और जब तक इस क्षेत्र को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो आशा की किरण दिखाई नहीं देगी। यह भी सच है कि कृषि क्षेत्र की स्थिति इतनी दयनीय नहीं है, इसके लिए हमें कम अवधि या सीमित समय में परिणामों की आशा से बचना होगा।

अब वापसी करते हुये में कहना चाहूँगा कि भारतीय कृषि की कहानी एक असफलता नहीं है। इसकी बहुत सी सफल कहानियां हैं और पिछले 18 महीनों से जो मैंने देखा है उनमें से कुछ का उल्लेख करूँगा। निःसंदेह, हरित क्रांति ने 60 के दशक के सूखे से लेकर खाद्य आयात पर निर्भर रहने की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। अब भारत कृषि क्षेत्र में बिलकुल अलग मुकाम पर है।

इसी प्रकार से भारत में श्वेत क्रांति की कहानी है। जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सामान्य रूप से विकासशील देशों के लिए विदेशी सहायता अच्छी नहीं है। सस्ते अनाज के रूप में दी गई आर्थिक सहायता से पूरे संसार पर हानिकारक प्रभाव पडा है, विशेषकर अफ्रीका में। भारत की श्वेत क्रांति ने सामान्य नियम में बदलाव करते हुये सस्ती खाद्य वस्तुओं के आयात जैसे दूध का पाऊडर से हमारे देसी खाद्य क्षेत्र को विकसित करने में सहायता मिली है, शेष इतिहास बन चुका है। यह सफलता सामान्य अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार हैरान कर देने वाली है।

उस समय भारत के पास जिंसों के मूल्य बढ़ने की अवधि केवल 6 से 7 वर्ष थी। उस समय वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य काफी ऊँचे थे। किंतु, हम उस स्थिति को समझ नहीं पाए, अन्यथा हमारी भौगोलिक और कृषि विकास की गति काफी अधिक होती। हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और कुछ दक्षिणी राज्यों में लागू की गई थी, लेकिन पिछले 10 से 15 वर्षों में ही यह गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य-प्रदेश, कुछ सीमा तक बिहार में भी फैल चुकी है। इस प्रकार का विस्तार स्वागत योग्य है।

कई क्षेत्रों में अनाज के अतिरिक्त अन्य जिंसों का विकास भी किया गया है। गुजरात में कपास, महाराष्ट्र में बागवानी, पश्चिम बंगाल में आलू, बिहार में मक्का की कहानी और निःसंदेह मध्य-प्रदेश में पारंपरिक अनाज उगाने की कहानी सफलता का ब्यान करती है। इस विविधता के महत्व का पता चलता है कि भारतीय कृषि में कई स्थानों पर सूखा पड़ने के बावजूद भी प्रगति की गई है और हमारी कृषि लचीली प्रकृति की बनती जा रही है।

यदि वर्षा की मात्रा और खाद्य उत्पादन के बीच संबंध की बात करें तो वर्ष 2015 में बहुत कम बरसात हुई थी। वास्तव में यह दूसरा वर्ष था जब कम वर्षा हुई और सामान्य स्थिति में इस कमी के कारण हमारा खाद्य और कृषि उत्पादन प्रभावित होना चाहिये था, लेकिन इस क्षेत्र में जो परिणाम आया वह वृद्धि लिए हुए था और ऐसी वृद्धि 10-15 वर्ष पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। सार यह है कि कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के बाद भी भारतीय कृषि एक सफल कहानी कहती है।

मूल रूप से कृषि से संबंधित दो प्रमुख मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है: कृषि आय और इसकी आजीविका में वृद्धि करना। इन दोनों का संबंध कृषि उत्पादकता से है। लेकिन विश्व में कृषि उत्पादकता के मामले में भारत निराश करता है और प्रति श्रमिक को दी जाने वाली आय की भी यही कहानी है, जबकि चीन, ब्राजील, यूरोप और अमेरिका की तुलना में मजदूरी बहुत कम है। चीन की उत्पादकता भारत की तुलना में 3.7 गुना अधिक, ब्राजील की 7 गुना, यूरोप की 52 गुना और अमेरिका की लगभग 100 गुना अधिक उत्पादकता है। वास्तव में इस दूरी को समाप्त करने से ही भारतीय कृषि की आजीविका बढ़ाई जा सकती है।

प्रत्येक संबंधित को अपने दिमाग में एक विरोधाभास रखना चाहिये की भारत को कृषि उत्पादकता में सुधार करने के साथ-साथ लोगों को कृषि क्षेत्र से निकालकर अन्य क्षेत्रों में लगाने का प्रयास करना चाहिये। पूरे विश्व में विकास की कहानी उन लोगों की कहानी है जो कृषि छोड़कर अन्य अधिक आय देने वाले कार्यों में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहने का तात्पर्य कृषि के महत्व और योगदान को कम करना नहीं है बल्कि यह कहना है कि लंबे समय में कृषि क्षेत्र में निहित सीमाएं होने के कारण हमें अन्य क्षेत्रों को तलाशना होगा।

यदि कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसे उच्च आय प्रदान करने वाले व्यवसाय में जाना चाहिये। अतः कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाने के साथ-साथ लोगों को बड़े पैमाने पर कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में शामिल करना होगा, लेकिन अच्छी स्थितियों के अंतर्गत ही। उन्हें कृषि में कम उत्पादकता है आधार पर ही कृषि छोड़ने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।

आंध्र-प्रदेश के कृष्णा जिले में यह देखा जा सकता है कि डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर और जन-धन योजना, आधार और मोबाईल नंबर की क्रांति से कितना लाभ हुआ है। कृष्णा जिले में दिखाई देता है कि इन योजनाओं से क्या-क्या लाभ लिए जा सकते हैं, सामूहिक वित्त शामिल करना, बायोमैट्रिक और मोबाईल के उपयोग से निर्धनों की सहायता करना। इस क्षेत्र के दौरे की समाप्ति पर मैंने एक जिलाधिकारी से कहा कि मैं इन योजनाओं से बहुत प्रभावित हूँ और पूछा कि कृष्णा जिले में प्रति व्यक्ति आय क्या है। उन्होंने बताया कि रु. 1.1 लाख, जो कि बहुत कम है।

एक उपजाऊ क्षेत्र जैसे कृष्णा जिला की भी बहुत कम औसत आय है क्योंकि अधिकतम लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। अतः यह विश्वास किया जाता है कि कृषि क्षेत्र को छोड़कर ही अधिक आय प्राप्त की जा सकती है और एक सामान्य ग्रामीण भारतीय को क्षेत्र परिवर्तन करना होगा। माओ ने लोकप्रिय बात कही है कि, 'इस क्षेत्र से बाहर निकलकर उद्योग को अपना ही महत्वपूर्ण उपाय है'। यहां विचारणीय बिंदु यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कृषि आजीविका का एक स्थाई साधन नहीं बन सकती है।

दूसरा प्रमुख लक्ष्य, कृषि क्षेत्र एक अस्थिर क्षेत्र होने के कारण सरकार द्वारा किसानों को इस अनिश्चित और जौखिम भरे कृषि व्यवसाय से बचाना चाहिये। भारत और चीन की कृषि वृद्धि दर की तुलना करने के लिए कहना न होगा कि दोनों का कृषि क्षेत्र अस्थिर था किंतु चीन ने पिछले 10 या 15 वर्षों में स्थिरता प्राप्त कर ली

है। जबकि भारत अभी भी अस्थिरता का सामना कर रहा है। भारत के लिए बड़ी चुनौती है, न केवल उत्पादकता बढ़ाने की अपितु किसानों को उनकी दयनीय स्थिति से भी उभारना है। इसी कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की गई है।

उत्पादकता बढ़ाने और जौखिम कम करने के इन दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति करना मालथस सिद्धांत को झूठा साबित करना होगा। मूल कृषि संसाधन, पानी, भूमि, मिट्टी की गुणवत्ता और वातावरण सभी दुर्लभ और दूषित होते जा रहे हैं, इसका कारण जलवायु परिवर्तन – विश्व में परिवर्तित मौसम की स्थिति के कारण – और आंशिक रूप से इंसान द्वारा स्वयं साधनों को नष्ट करना है।

भारत की घरेलू नितियों से भी कुछ अनिवार्य संसाधनों में कमी आती जा रही है : कतिपय कारणों से भूमि की गुणवत्ता से क्षिण होती जा रही है, जल स्तर निचे जाता जा रहा है, और यह सब 15–20 वर्ष पहले तक नहीं था, किंतु अब तो परिपेक्ष्य ही बदलता जा रहा है। भारत ने कई सफलताएँ प्राप्त की हैं किंतु आज कई चुनौतियाँ हैं, विशेषकर पर्यावरण के क्षेत्र में जिनमें कठिनाईयाँ बढ़ती जा रही हैं। प्रश्न है कि क्या करने की आवश्यकता है ? कई विकल्प हो सकते हैं, कई विचार भी हो सकते हैं और सभी ठिक भी हो सकते हैं।

मैं जल्दी से क्या करने की आवश्यकता है उसका उल्लेख करूँगा क्योंकि मैं एक अधिक मूल और गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए आपके पास मुझसे बेहतर उत्तर होंगे। पहले, कृषि क्षेत्र से अधिक उत्पादन लेने के लिए अधिक देने का मामला था : जैसे, अधिक उर्वरक, अधिक पानी, अधिक बिजली ताकि अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सके। आज परिवर्तित वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति को कम व्यय करके अधिक प्राप्त करने की पद्धति है, जैसे की उपकरणों का सही प्रकार से उपयोग करके – चाहे बिजली, उर्वरक अथवा भूमि को।

हमें कृषि क्षेत्र के लिए ही एक मार्केट बनाने की भी आवश्यकता है, और राष्ट्रीय कृषि मार्केट, जिस पर सरकार कार्य कर रही है और उसी दिशा में अग्रसर भी है। कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका कम करने की आवश्यकता है, फसल और कृषि बीमा को मजबूत किया जाए, इसके साथ भूमि का अधिकतम उपयोग, विशेषकर छोटे-छोटे खेतों को मिलाना चाहिए, जिसके कारण कृषि उत्पादकता बढ़ नहीं पा रही है, इसके लिए भूमि संकलन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। निति आयोग भी एक आदर्श कानून पट्टे की भूमि के संबंध में बना रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। विज्ञान की भूमिका बढ़ाने और उन्नत घरेलू अनुसंधान एवम् विकास क्षमता में सुधार करने की भी आवश्यकता है क्योंकि भारत में अब दालों के लिए इन्द्रधनुषी क्रांति की आवश्यकता है।

वास्तव में, कई प्रकार की नीति अनिश्चिताएँ हैं, विशेषकर कृषि मूल्यों के बारे में। जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ते हैं तो नीतियों का एक सेट अपना लिया जाता है। जब कृषि मूल्य निचे गिरते हैं तो दूसरा सेट अपनाया जाता है, जिस कारण लंबे समय में किसान ही हानि उठाते हैं। जिसका मूल कारण ऐसी नीति अनिश्चिताओं का होना है। ऐसी परिस्थितियों में किसान दीर्घ कालिक निर्णय नहीं ले पाते। क्या उन्हें रु. 100, रु. 300, रु. 400 के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर प्याज उगाने का निर्णय करना चाहिए, अथवा शून्य निर्यात मूल्य पर।

संस्थाओं को संगठित करने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, जैसा शांताकुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय खाद्य निगम और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को मजबूत किया जाए और इसी प्रकार ही अन्य संस्थाओं के बारे में भी विचार किया जाए। कृषि ऋण को सुसंगठित करना होगा और इस संबंध में रामकुमार

और चव्हाण द्वारा किया गया अध्यन्न बहुत रुचिकर है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कृषि ऋण की बात कही गई है, जो न तो कृषि के लिए और न ही छोटे किसानों तक पहुंच रहा है। बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। इनकी सूची समाप्त होने वाली नहीं है और कोई भी इसमें प्रश्न जोड़ सकता है, लेकिन मैं आप सभी से एक उच्च और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

यदि मैं कहूँ की जल संरक्षण में सुधार करना चाहिए अथवा नीति संबंधी अनिश्चिताएँ समाप्त की जाएँ तो प्रश्न तुरंत होगा की ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ? एक गहन प्रश्न है – देश में एक अच्छी कृषि नीति या अच्छी राज्यस्तरीय राजनीति क्यों नहीं है ? आप कृषि वृद्धि को देखें और जाने की गुजरात, मध्य-प्रदेश, बिहार अथवा पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में क्या हुआ है, इन सभी में एक समानता है कि इन राज्यों की सरकारें पुनः निर्वाचित हुई हैं और कृषि क्षेत्र प्रगति पर है।

भारत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही हैं, विशेषकर अच्छी कृषि नितियां बनाकर, अच्छी राजनीति करके। लेकिन यह सब बड़े पैमाने पर क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत साधारण प्रश्न है। चुनाव में इसका परिणाम देखने को क्यों नहीं मिलता क्योंकि सूखा पडने की स्थिति में कुछ नहीं किया जाता, जिस कारण कई किसान कष्ट उठाते हैं। कृषि क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऐसे संकट की स्थिति में आवश्यकताओं की पूर्ति करके अच्छी राजनीति की जानी चाहिए। जिसके लिए लाखों लोगों और लाखों किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है। यह एक बड़ी दुविधा है।

जल संरक्षण में निवेश इतना कम क्यों है ? कृषि उपज विपण समितियों को समाप्त करने में ऐसी कौन सी कठिनाई है, जबकि ऐसा करने से देश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। यह कुछ लोगों का प्रश्न है, जबकि लाखों लोगों का भाग्य दांव पर है, इस कारण चुनावी/लोकतांत्रिक राजनीति में अधिक संख्या वालों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी जीत होनी चाहिए। गुजरात में बीटी कपास की सराहनीय सफलता को देश के अन्य भागों में क्यों नहीं अपनाया जा रहा। सभी जानते हैं कि विरोध कहां से हो रहा है, किंतु यह तो प्रत्यक्ष सफलता का नमूना है। इसका विस्तार क्यों नहीं करना चाहिए।

मैं एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूँ। निजी क्षेत्र से किस बात का भय है, जबकि बहुत से निजी क्षेत्र मक्का, बीटी कपास, बाजरा आदि सफलता पूर्वक उगा रहे हैं। कृषि में इस प्रकार का प्रयोग करने में हिचकिचाहट क्यों है। एक अन्य बिंदु मस्तिष्क में तब आया जब मेरे दल ने उर्वरक पर अनुसंधान किया, जैसा हमने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा, उर्वरक नीति ने वास्तव में छोटे किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है क्योंकि इसकी कालाबाजारी है और इससे छोटे किसान ही प्रभावित होते हैं, जबकि बड़े किसानों को अधिक हानि नहीं पहुंचती। ऐसी ही स्थिति बीजों की भी है।

ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी छोटे किसानों की संख्या होने के बाद भी राजनीति में छोटे किसानों या निर्धन व्यक्तियों के लिए लाभकारी योजनाएँ तैयार क्यों नहीं की जा रही। ये कुछ बड़े प्रश्न हैं, जिनका समाधान करने की सिफारिशें करने से पहले इन पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। समाचार पत्र रोजाना परामर्श देते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए, लेकिन यही मुद्दा चुनावी राजनीति में प्रमुख मुद्दा क्यों नहीं बनता, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने की आवश्यकता है।

सरकार क्या कर सकती है, ऐसी बातों की चिंता करने के स्थान पर निम्नलिखित प्रयोगों पर विचार किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में यदि सरकार केवल दो मूल बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करे, पहला, एक बड़ा

सार्वजनिक निवेश जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अनुसंधान एवम् विकास, सेवाओं का विस्तार, हरित क्रांति के माध्यम से असली सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति करना। यह सब तकनीकी और कृषि विस्तार सेवाओं के बारे में है किंतु आज सेवाओं के विस्तार की स्थिति पर तो एक नजर डालें।

हो सकता है कि सरकार को कई सार्वजनिक वस्तुएँ और सार्वजनिक निवेश उपलब्ध कराने पर ही ध्यान देना चाहिए और लोगों को महसूस करना चाहिए कि, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कृषि क्षेत्र प्रयाप्त आजीविका नहीं दे सकता है। अतः कुछ मूल आय के रूप में सहायता जैसे उपाय भी करने होंगे। में कोई रेखा नहीं खिंचना चाहता लेकिन कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है कि कृषि अव्यवहारिक है, क्योंकि इसकी उत्पादकता कम है, लाभ बहुत कम है। इस कारण लोगों को अन्य प्रकार के सेवा क्षेत्र उपलब्ध करवाने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इन सब चिजों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके बड़ी सहायता कर सकता है और कृषि को समृद्धशाली एवम् इसके उच्च स्तर पर पहुंचाने में भी सहायक हो सकता है। यह केवल एक मूल और महत्वपूर्ण विचार है, जिसे में आप पर छोड़ता हूँ।

कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। सबसे पहले इस क्षेत्र की राजनीति समाप्त करनी होगी, लेकिन कुछ अन्य पहलू भी हैं। एक सामान्य नियम है कि संकट या आवश्यकता सुधारों या आविष्कार की जननी है। इसी प्रकार का परिवर्तन भारत ने वर्ष 1991 में देखा है। चालू बजट में दिखाई देता है कि कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए कई उपाय किये गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि भी बढ़ाई गई है, पिछले 2-3 वर्षों की तुलना में दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी काफी बढ़ाए गए हैं। क्योंकि दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी आरंभ की गई है और कृषि क्षेत्र को भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोल दिया गया है।

कुछ क्षेत्रों में संकट के कारण सकारात्मक उपाय किये गए हैं और समस्याओं के समाधान के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकि है। यदि लगातार दो अच्छे मॉनसून आ जाएं, जैसा हर कोई चाहता है, तो कृषि के भाग्य में स्थाई रूप से सुधार हो सकता है और यह संभव होगा कि इस क्षेत्र पर दीर्घकालिक ध्यान दिया जा सके, क्योंकि भविष्य में बहुत से क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

में अपनी बात एक वाक्य में समाप्त करना चाहूँगा कि अर्थशास्त्रियों का इस कारोबार में कोई विशेष स्थान नहीं है। रॉबर्ट सोलो, एक नोबल पुरस्कार विजेता ने एक बार कहा था कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि पर अधिकतम वार्तालाप शैक्षिक महत्व पर निर्भर करता है, और इसकी समाप्ति एक शौकिया समाज शास्त्र के रूप में हो जाती है। कृषि के बारे में एक गहन समस्या है कि यह क्षेत्र लोगों के दिमाग अपनी छाप नहीं छोड़ता है। जैसे, पहले कभी कृषि क्षेत्र लाभकारी था, इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में बड़ी प्रतिभाएँ भी आकर्षित नहीं होती। कृषि क्षेत्र में एम.एस. स्वामीनाथन, सी. सुब्रमनियन, महान शिक्षा अर्थशास्त्री, के.एन. राज, राजकृष्णा अथवा प्रतिष्ठित वरगिस कुरियन जैसे अन्य प्रतिभासंपन्न व्यक्ति अब इस क्षेत्र के प्रति क्यों आकर्षित नहीं हो रहे।

कृषि का संचालन पहले बड़े-बड़े विद्वानों, प्रतिष्ठित विज्ञानिकों अथवा किसानों और राजनैताओं द्वारा किया जाता था। कृषि के समाज शास्त्र को कुछ न कुछ ऐसा हो चुका है कि जो आकर्षण इसमें पहले था, वैसा आकर्षण अब नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ न कुछ असंगत हो चुका है, जब तक उसे सुधारा नहीं जाता तब तक भारतीय कृषि संघर्ष करती रहेगी और यह एक शर्मनाक घटना होगी, क्योंकि भारत में कृषि आजीविका का पुर्नउत्थान अतिआवश्यक है। सम्पूर्ण रूप में देश के लिए इस क्षेत्र को कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए।*